दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय की तिथि:11.09.2009

रि.या.(सि.)2887/2008

एस.एम.टी. हर नारायणी देवी और अन्य| .....याचीगण

बनाम

भारत संघ व अन्य ..... प्रत्यर्थीगण

इस मामले में पेश हुए अधिवक्ताः

याचीगण के लिए :श्रीमती संतोष सिंहः राकेश मुद्गल
प्रत्यर्थीगण संख्या 1&2 के लिए :श्री गौरव दुग्गल
प्रत्यर्थीगण संख्या3 और 4 के लिए :श्री आनंद यादव

कोरमः
माननीय न्यायाधीश बदर दुर्रेज़ अहमद
माननीय न्यायाधीश वीना बीरबल

1. क्या स्थानीय समाचार पत्रों के संवाददाताओं को निर्णय देखने की अनुमति दी जा सकती है? हाँ

2. रिपोर्टर के पास प्रेषित किया जाना है या नहीं? हाँ

3.क्या निर्णय को डाइजैस्ट में प्रकाशित किया जाना चाहिए? हाँ

बदर दुर्रेज़ अहमद

1. इस रिट याचिका द्वारा , याचीगण ने मांग की है कि दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 50 (जिसे इसके बाद "उक्त अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) के खंड (ए) को असंवैधानिक घोषित किया जाए, जो कथित रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के विपरीत है।

2. याचीगण स्वर्गीय श्री ईश्वर सिंह (1985 में निधन) के पुत्र स्वर्गीय श्री मुख्तियार सिंह (6.6.97 पर निधन) की विधवा और बेटी हैं। स्वर्गीय श्री ईश्वर सिंह के दो बेटे भी थे, जो प्रत्यर्थी संख्या 3 और 4 हैं।

3. स्वर्गीय श्री मुख्तियार सिंह कुछ भूमि के संबंध में भूमिधर थे जो उक्त अधिनियम द्वारा शासित थीं। उक्त अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों के अनुसार, उनकी मृत्यु पर, उक्त जोत में उनका भूमिधारी हित उनके पोते, प्रत्यर्थी संख्या 3 और 4 को हस्तांतरित किया गया। उक्त अधिनियम की धारा 50 यहाँ नीचे पुनः प्रस्तुत की गई हैः

> **“50. पुरुषों से उत्तराधिकार का सामान्य आदेश।-** विषय के अधीन धारा 48 और 52 के प्रावधान, जब कोई भूमिधर या आसामी पुरुष होने के नाते मर जाता है, तो उसकी हिस्सेदारी में उसका हित नीचे दिए गए उत्तराधिकार के आदेश के अनुसार हस्तांतरित होगाः
>
> (क) वंश के पुरुष वंश में पुरुष वंशावलीः
>
> बशर्ते कि इस वर्ग का कोई भी सदस्य उत्तराधिकारी नहीं होगा यदि उसके और मृतक के बीच कोई पुरुष वंशज जीवित हैः

बशर्ते कि किसी पूर्व मृत पुत्र का पुत्र या पुत्र, चाहे वह कितना भी कम क्यों न हो, उस हिस्से का उत्तराधिकारी होगा जो मृतक को हस्तांतरित होता यदि वह तब जीवित होता:

(ख) विधवा;

(ग) पिता;

(घ) माता, विधवा होने के नाते;

(ङ) सौतेली माँ, विधवा होने के नाते;

(च) पिता के पिता;

(छ) पिता की माँ, विधवा होने के नाते;

(ज) वंश के पुरुष वंश में एक पुरुष वंश की विधवा;

(झ) भाई, जो मृतक के पिता का पुत्र है;

(ट) अविवाहित बहन;

(ञ) भाई का बेटा, भाई उसी पिता का बेटा है जो मृतक है;

(ट) पिता का पुत्र;

(ठ) भाई का पुत्र;

(ड) पिता का पुत्र;

(ढ) बेटी का पुत्र।"

(रेखांकित करना जोड़ा गया)

4. याचीगण की मुख्य शिकायत धारा 50 में प्रदान की गई उत्तराधिकार की रेखा के संबंध में है। इसके धारा (क) में यह अपेक्षा की गई है कि जब भी किसी पुरुष भूमिधर या आसामी की मृत्यु हो जाती है, तो ब्याज पहले पुरुष वंशावली के पुरुष वंशजों को दिया जाएगा, चाहे वह कितना भी कम क्यों न हो, इस प्रकार महिला वंशजों को छोड़कर। इस तथ्य को देखते हुए कि कोई पुरुष वंश नहीं होने की संभावना बहुत कम है, सभी संभावनाओं में ब्याज किसी भी मामले में महिला वंशजों पर नहीं जाएगा। मृतक की विधवा (याचिकाकर्ता संख्या 1) का उल्लेख धारा (ज) में किया गया है और पोती (याचिकाकर्ता संख्या 2) को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। लिंग के आधार पर भेदभाव के आधार पर याचिकाकर्ता उक्त प्रावधान को चुनौती दे रहे हैं।

5. प्रत्यर्थियों ने अपने विद्वान अधिवक्ता द्वारा से वर्तमान याचिका की स्थिरता के संबंध में इस आधार पर प्रारंभिक आपत्ति जताई है कि उक्त अधिनियम को संविधान (सत्रहवां संशोधन) अधिनियम, 1964 के आधार पर भारत के संविधान की नौवीं अनुसूची (प्रविष्टि 61 में) में रखा गया था। संविधान के अनुच्छेद 31ख में प्रावधान है कि नौवीं अनुसूची में रखा गया कोई भी अधिनियम चुनौती का विषय नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 3झ ख निम्नानुसार हैः-

> **"अनुच्छेद 31ख. कुछ अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन।-** पूर्वाग्रह के बिना अनुच्छेद 31क में निहित प्रावधानों की व्यापकता के अनुसार, नौवीं अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी अधिनियम और विनियम या उसके किसी भी प्रावधान को इस आधार पर शून्य नहीं माना जाएगा कि ऐसा अधिनियम, विनियम या प्रावधान इस भाग के किसी भी प्रावधान द्वारा प्रदत्त किसी अधिकार को न्यून करता है या उसे छीन लेता है या कम करता है, और इसके विपरीत किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के

किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के बावजूद, उक्त अधिनियमों और विनियमों में से प्रत्येक, किसी भी सक्षम विधानमंडल की इसे निरस्त करने या संशोधित करने की शक्ति के अधीन रहते हुए, लागू रहेगा।"

6. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने संविधान पीठ पर भरोसा किया वामन राव बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णयः ए.आई.आर 1981 स.मु. **271 , जिसमें, केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ इंडिया में उनके पहले के निर्णय पर विचार करते हुए केरलः ए.आई.आर. 1973 स.मु. 1461, अदालत ने फैसला सुनाया किः-**

"2. केशवानंद भारती में, 24 अप्रैल, 1973 को निर्णय लिया गया कि बहुमत द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं है ताकि इसकी बुनियादी या आवश्यक विशेषताओं या इसकी मूल संरचना को नुकसान पहुंचाया जा सके और नष्ट किया जा सके। हमारा मानना है कि संविधान में सभी संशोधन जो 24 अप्रैल, 1973 से पहले किए गए थे और जिनके द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची में विभिन्न अधिनियमों और विनियमों को शामिल करके समय-समय पर संशोधन किया गया था, वैध और संवैधानिक हैं। 24 अप्रैल, 1973 को या उसके पश्चात किए गए संविधान में संशोधन, जिसके द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची में विभिन्न अधिनियमों और विनियमों को शामिल करके समय-समय पर संशोधन किया गया था, इस आधार पर चुनौती देने के लिए खुले हैं कि वे, या उनमें से कोई भी एक या अधिक, संसद की घटक शक्ति से परे हैं क्योंकि वे संविधान या इसकी मूल संरचना की बुनियादी या आवश्यक विशेषताओं को नुकसान पहुंचाते हैं। हम इस तरह बाद के संवैधानिक संशोधनों की वैधता पर यह कहने के अलावा कुछ नहीं कहते हैं कि यदि कोई अधिनियम या विनियमन 24 अप्रैल के पश्चात किए गए संवैधानिक संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 1973 को अनुच्छेद 31ग द्वारा बचाया गया है क्योंकि यह 42वें संशोधन द्वारा इसके संशोधन से पहले था, प्रासंगिक

> संवैधानिक संशोधन की वैधता को चुनौती, जिसके द्वारा उस अधिनियम या विनियमन को 9वीं अनुसूची में रखा गया है, इस आधार पर कि संशोधन संविधान या इसकी मूल संरचना को नुकसान पहुंचाता है या नष्ट कर देता है जैसा कि अनुच्छेद 14,19 या 31 में परिलक्षित होता है, अनुचित हो जाएगा।"
>
> (रेखांकित करना जोड़ा गया)

7. तदनुसार, प्रत्यर्थीगण के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि चूंकि उक्त अधिनियम को 24.4.1973 (अर्थात 1964 में) से पहले नौवीं अनुसूची में रखा गया था, इसलिए यह अनुच्छेद 31बी में प्रदान की गई प्रतिरक्षा द्वारा कवर किया गया है, और इस प्रकार, चुनौती के दायरे से परे है। नतीजतन, उन्होंने प्रस्तुत किया, वर्तमान याचिका बनाए रखने योग्य नहीं है।

8. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने आई. आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में उच्चतम न्यायालय के हाल के नौ-न्यायाधीशों की पीठ के एक अन्य फैसले पर भरोसा व्यक्त कियाः(2007) 2 स.मु.मु. 1, जिसमें न्यायालय ने टिप्पणी कीः

> "136. <u>न्यायपालिका की भूमिका मूल अधिकार की रक्षा करना है। एक आधुनिक लोकतंत्र बहुसंख्यक शासन के दोहरे सिद्धांतों और मूल अधिकार की रक्षा करने की आवश्यकता पर आधारित है।</u> लॉर्ड स्टाइन के अनुसार, यह न्यायपालिका का काम है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए सिद्धांतों को संतुलित करे कि संख्या के आधार पर सरकार मूल अधिकार पर हावी न हो।
>
> ***बुनियादी संरचना के सिद्धांत का अनुप्रयोग***

137. केशवानंद भारती के मामले में, चर्चा अनुच्छेद 368 द्वारा प्रदत्त संशोधन शक्ति पर थी, जिसमें 'घटक शक्ति' शब्दों का उपयोग नहीं किया गया था।हम संविधान बनाने की मूल शक्ति जिसे घटक शक्ति के रूप में जाना जाता है और अनुच्छेद 368 के तहत संसद में निहित घटक शक्ति की प्रकृति के बीच अंतर को पहले ही देख चुके हैं। अनुच्छेद 368 में 'घटक शक्ति' शब्दों को जोड़ने से, संशोधन करने वाला निकाय, अर्थात् संसद मूल संविधान सभा नहीं बन जाती है। यह एक नियंत्रित संविधान के तहत एक संसद बनी हुई है। अनुच्छेद 368 में 'घटक शक्ति' शब्द जोड़े जाने के बाद भी, बुनियादी संरचना के सिद्धांत की सीमाएँ संसद पर लागू होती रहेंगी। इसी आधार पर मिनर्वा मिल्स में 42वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में अंतः स्थापित धारा 4 और 5 को निरस्त कर दिया गया था।

मामला।

138. इंदिरा गांधी के मामले, मिनर्वा मिल्स मामले की प्रासंगिकता और वामन राव का मामला इस तथ्य में निहित है कि संसद द्वारा अपनी शक्ति की प्रत्येक अनुचित वृद्धि, चाहे वह अनुच्छेद 329क की धारा 4 हो या अनुच्छेद 368 की धारा 4 और 5 या 42वें संशोधन की धारा 4 हो, को मूल संरचना के सिद्धांत के साथ असंगत माना गया है क्योंकि उन्होंने नए तत्वों को पेश किया है जिन्होंने संविधान की पहचान को बदल दिया है या संविधान से मौजूदा तत्वों को हटा दिया है जिसके द्वारा संविधान के मूल को त्याग दिया गया है। उन्होंने न्यायिक समीक्षा जैसे महत्वपूर्ण तत्वों को मिटा दिया। उन्होंने सभी मूल अधिकार के उन्मूलन के लिए निर्देशात्मक सिद्धांतों को एक कसौटी बनाया और नौवीं अनुसूची में कानूनों को शामिल करने का प्रावधान किया, जिनका कृषि सुधारों के साथ कोई संबंध नहीं था। यह इस संदर्भ में है कि हमें यह ध्यान में रखते हुए प्रतिरक्षा की शक्ति की जांच करनी होगी कि केशवानंद भारती के मामले के बाद, अनुच्छेद 368 निम्नलिखित के अधीन है -

मूल संरचना की निहित सीमा।

139. वामन राव के मामले में जिस प्रश्न की जांच की गई, वह यह था कि क्या अनुच्छेद 31ख के उपकरण का उपयोग नौवीं अनुसूची के कानूनों को न्यायिक समीक्षा से मुक्त करने के लिए किया जा सकता है, ताकि पूरे भाग III को ऐसे कानूनों पर लागू न किया जा सके और क्या ऐसी शक्ति बुनियादी संरचना सिद्धांत के साथ असंगत थी। जवाब सकारात्मक था। यह कहा गया है कि इससे नियंत्रित संविधान के अनियंत्रित होने की संभावना है। यह बुनियादी संरचना के सिद्धांत को निरर्थक बना देगा। यह नौवीं अनुसूची कानूनों की वैधता की जांच करने के लिए अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के साथ पठित अनुच्छेद 21 के स्वर्ण त्रिकोण को पूरी तरह से हटा देगा क्योंकि यह पूरे भाग III को संसद की इच्छा पर लागू नहीं करता है। इसके परिणामस्वरूप संविधान की पहचान में परिवर्तन होता है जो न केवल बुनियादी संरचना के सिद्धांत के साथ असंगतता लाता है, बल्कि संविधान में संशोधन करने की सीमित शक्ति के अस्तित्व के साथ भी असंगतता लाता है। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए न्यायिक समीक्षा की सीमा की जांच की जानी चाहिए।

140. अनुच्छेद 31बी के पीछे का उद्देश्य कठिनाइयों को दूर करना है और भाग III को पूरी तरह से या न्यायिक समीक्षा में मिटाना नहीं है। बुनियादी संरचना का सिद्धांत बुनियादी विशेषताओं को बचाने के लिए प्रस्तावित किया गया है। अनुच्छेद 21 संविधान का मूल है।यह जीवन के अधिकार के साथ-साथ चुनने का अधिकार भी प्रदान करता है। जब अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के साथ पठित अनुच्छेद 21 के इस त्रिकोण को समाप्त करने की कोशिश की जाती है, तो न केवल 'अधिकार का सार' परीक्षण बल्कि 'अधिकार परीक्षण' भी लागू होना चाहिए। विशेष रूप से जब केशवानंद भारती और इंदिरा गांधी के मामले कुछ मूल अधिकारों को भी शामिल करने के लिए बुनियादी संरचना के दायरे का विस्तार किया है।

(रेखांकित करना जोड़ा गया)

9. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में न्यायिक समीक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला और वामन राव मामले में निर्णय में कमियों की ओर इशारा किया, जिसे उन्होंने उस निर्णय के निहितार्थ को कम करके सुधारने की मांग की।तदनुसार, अदालत ने कहाः

"151. अंत में, हम मानते हैं किः

(i) संविधान के भाग III द्वारा गारंटीकृत अधिकारों को निरस्त या कम करने वाला कानून मूल संरचना सिद्धांत का उल्लंघन कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। यदि पहली विधि का परिणाम है, चाहे वह भाग III के किसी अनुच्छेद के संशोधन द्वारा हो या नौवीं अनुसूची में सम्मिलित करके, तो ऐसी विधि को न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति का प्रयोग करते हुए अमान्य करना होगा। वैधता या अयोग्यता का परीक्षण इस निर्णय में निर्धारित सिद्धांतों पर किया जाएगा।

(ii) इंदिरा गांधी के मामले के साथ पढ़े गए केशवानंद भारती के मामले में बहुमत के फैसले के लिए प्रत्येक नए संवैधानिक संशोधन की वैधता को उसके गुण-दोष के आधार पर आंका जाना आवश्यक है। यह निर्धारित करने के लिए कि यह बुनियादी संरचना को नष्ट करता है या नहीं, भाग III के तहत गारंटीकृत अधिकारों पर कानून के वास्तविक प्रभाव और प्रभाव को ध्यान में रखा जाना चाहिए। प्रभाव परीक्षण चुनौती की वैधता निर्धारित करेगा।

(iii) 24 अप्रैल, 1973 को या उसके बाद किए गए संविधान के सभी संशोधन, जिनके द्वारा नौवीं अनुसूची में विभिन्न कानूनों को शामिल करके संशोधन किया गया है, का परीक्षण संविधान की बुनियादी या आवश्यक विशेषताओं की कसौटी पर किया जाना चाहिए, जैसा कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 के साथ पठित अनुच्छेद 21 में परिलक्षित होता है और उनमें

अंतर्निहित सिद्धांत। इसे अलग तरह से कहने के लिए, भले ही एक अधिनियम को एक संवैधानिक संशोधन द्वारा नौवीं अनुसूची में रखा गया हो, इसके प्रावधान इस आधार पर हमला करने के लिए खुले होंगे कि वे मूल संरचना को नष्ट या नुकसान पहुंचाते हैं यदि मौलिक अधिकार या अधिकार छीन लिए गए हैं या निरस्त किए गए हैं या मूल संरचना से संबंधित हैं या संबंधित हैं।

(iv) संवैधानिक संशोधनों द्वारा नौवीं अनुसूची में शामिल कानूनों को संरक्षण प्रदान करने के लिए, पूर्ण संरक्षण नहीं, संवैधानिक निर्णय का विषय होगा, एक अधिनियम द्वारा मौलिक अधिकार के उल्लंघन की प्रकृति और सीमा की जांच करके, जिसे संवैधानिक रूप से संरक्षित किया जाना चाहिए, और मूल संरचना सिद्धांत की कसौटी पर, जैसा कि अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के साथ पठित अनुच्छेद 21 में परिलक्षित होता है, "अधिकार परीक्षण" और "अधिकार के सार" परीक्षण को लागू करके, जैसा कि इंदिरा गांधी के मामले में भाग III में अनुच्छेद के संक्षिप्त दृष्टिकोण को लेते हुए। उपरोक्त परीक्षणों को नौवीं अनुसूची के कानूनों में लागू करते हुए, यदि उल्लंघन मूल संरचना को प्रभावित करता है तो ऐसे कानून (ण) को नौवीं अनुसूची का संरक्षण नहीं मिलेगा।"

(रेखांकित करना जोड़ा गया)

10. याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि **वामन राव के मामले** (उपर्युक्त) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को **आई.आर. कोएल्हो के मामले** (उपर्युक्त) में निर्णय द्वारा इस अर्थ में कम कर दिया गया था कि कोई भी अधिनियम या विनियमन और उसके प्रावधान, जो अनुच्छेद 14,19 और 21 के अनुसार नागरिकों के मूल अधिकार को छीनकर या निरस्त करके संविधान के मूल ढांचे को नष्ट या क्षतिग्रस्त करते हैं, चुनौती देने के लिए खुले हैं, सभी संशोधनों पर लागू होंगे, चाहे

वे पहले किए गए हों या बाद में किए गए हों। यह प्रस्तुत किया गया था कि चूंकि धारा 50 (ए) अनुच्छेद 14,15 और 21 का स्पष्ट उल्लंघन है, इसलिए इसे निरस्त किया जाना चाहिए।

11. इस प्रकार, इस न्यायालय द्वारा तय किया जाने वाला मौलिक प्रश्न यह है कि क्या उक्त अधिनियम की धारा 50 (क) के प्रावधान चुनौती का विषय हो सकते हैं, जब इसे 1964 में संविधान के सत्रहवें संशोधन अधिनियम के आधार पर नौवीं अनुसूची में रखा गया था?

12. **वामन राव के मामले** (उपर्युक्त) में निर्णय पर विचार करते हुए, यह स्पष्ट है कि 1973 से पहले के संशोधनों के आधार पर नौवीं अनुसूची में रखे गए अधिनियम किसी भी आधार पर चुनौती का विषय नहीं हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में, वे निर्विघ्न रहते हैं। **आई.आर. कोएल्हो** के मामले में फैसले के अधिक विस्तृत अध्ययन से भी यही पता चलता है।निर्णय के प्रासंगिक अनुच्छेदों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

> "1. इन मामलों में हमारा सामना 24 अप्रैल, 1973 के बाद किए गए संशोधनों द्वारा नौवीं अनुसूची में जोड़े गए कानूनों में भारत के संविधान, 1950 (संक्षेप में, 'संविधान') के अनुच्छेद 31-ख द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा की प्रकृति और चरित्र को निर्धारित करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन बहुत आसान कार्य से है। **इस तारीख की प्रासंगिकता इस कारण से है कि इस तारीख को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में निर्णय था संवैधानिक संशोधनों की वैधता का परीक्षण करने के लिए संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन करना।**
>
> XXXXXXXXXXXXXXXXX

<u>व्यापक सवाल</u>

5. **बुनियादी सवाल यह है कि क्या 24 अप्रैल, 1973 को और उसके बाद जब बुनियादी संरचना सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था, तो क्या संसद के लिए अनुच्छेद 31ख के तहत मूल अधिकार से कानूनों को प्रतिरक्षित करने की अनुमति है। उन्हें नौवीं अनुसूची में शामिल किया गया है** और यदि ऐसा है, तो न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है।"

(जोर दिया गया)

इसके अलावा, फैसले के समापन भाग को पढ़ना पीठ के इरादे को स्पष्ट करता है। वही, अन्य बातों के साथ साथ साथ, नीचे पढ़ा गया हैः-

"151. (iii) <u>24 अप्रैल, 1973 को या उसके बाद किए गए संविधान के सभी संशोधन, जिनके द्वारा नौवीं अनुसूची में विभिन्न कानूनों को शामिल करके संशोधन किया गया है, का परीक्षण संविधान की बुनियादी या आवश्यक विशेषताओं की कसौटी पर किया जाना चाहिए, जैसा कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 के साथ पठित अनुच्छेद 21 में परिलक्षित होता है और उनमें अंतर्निहित सिद्धांत।</u> इसे अलग तरह से कहने के लिए, भले ही एक अधिनियम को एक संवैधानिक संशोधन द्वारा नौवीं अनुसूची में रखा गया हो, इसके प्रावधान इस आधार पर हमला करने के लिए खुले होंगे कि वे मूल संरचना को नष्ट या नुकसान पहुंचाते हैं यदि मौलिक अधिकार या अधिकार छीन लिए गए हैं या निरस्त किए गए हैं या मूल संरचना से संबंधित हैं या संबंधित हैं।

(v) यदि इस न्यायालय द्वारा किसी भी नौवीं अनुसूची कानून की वैधता को पहले ही बरकरार रखा जा चुका है, तो इस निर्णय द्वारा घोषित सिद्धांतों पर ऐसी कानून को फिर से चुनौती देने के लिए खुला नहीं होगा। हालांकि, यदि भाग III में किसी भी अधिकार का उल्लंघन करने वाली किसी कानून को बाद में 24 अप्रैल, 1973 के पश्चात नौवीं अनुसूची में

> शामिल किया जाता है, तो इस तरह के उल्लंघन/विघ्नता को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि यह अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और उसके तहत अंतर्निहित सिद्धांतों के साथ पठित अनुच्छेद 21 में इंगित मूल संरचना को नष्ट या नुकसान पहुंचाता है।"

(रेखांकित करना जोड़ा गया)

13. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के दोनों निर्णय केशवानंद भारती के मामले (उपरोक्त) में निर्णय के पश्चात, यानी 24.04.1973 के पश्चात संवैधानिक संशोधनों पर लागू होते हैं। आई.आर. कोएल्हो (ऊपर) में ही आई.डी. 1 का महत्व इसलिए बताया गया है क्योंकि इस तारीख को ***केशवानंद भारती*** (उपर्युक्त) में निर्णय सुनाया गया था जिसने "मूल संरचना" सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तदनुसार, हम पाते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 50 (क) को संविधान के अनुच्छेद 31 बी के कारण और क्योंकि इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है इसे 1964 में संविधान की नौवीं अनुसूची में रखा गया था, यानी 24.04.1973 से पहले।

14. यद्यपि याचिकाकर्ताओं के लिए उक्त अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों से व्यथित होने का स्पष्ट औचित्य हो सकता है क्योंकि यह भूमिधर के पुरुष वंशजों के पक्ष में भारी है और यह महिलाओं के अधिकारों के प्रति अनुचित रूप से पूर्वाग्रहपूर्ण प्रतीत हो सकता है और इसे केवल लिंग के आधार पर उनके खिलाफ भेदभाव के रूप में माना जा सकता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा व्याख्या किए गए संवैधानिक प्रावधानों के मद्देनजर, इस अदालत के हाथ बंधे हुए हैं। शायद विधायिका को भूमिधरों और आसमियों की महिला वंशजों की असंगत स्थिति पर ध्यान देंना चाहिए और असमानता को दूर करना चाहिए।

15. अभी के लिए, हमें प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता से सहमत होना होगा, कि उक्त अधिनियम की धारा 50 को चुनौती देने वाली यह रिट याचिका विचारणीय नहीं है।

16. इसलिए रिट याचिका खारिज कर दी जाती है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

, न्या. बदर दुर्रेज़ अहमद

न्या. वीना बीरबल

सितंबर, 11, 2009

दीया

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*